

TODAY WEATHER



DAY

32°

Hi

NIGHT

28°

Low

संक्षेप

जम्मू-कश्मीर स्टेटहूड पर केंद्र की वादाखिलाफी, उमर अब्दुल्ला बोले- संघर्ष तो बस शुरू हुआ है

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध-प्रदर्शन को दबा दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से सम्मान और स्व-शासन के लिए उनके अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार बहाल करने का आंदोलन तो अभी शुरू ही हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने X पर एक पोस्ट में प्रदर्शन के दौरान आई चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि हमें जंतर-मंतर जाने और अपने जायज हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने से रोकना गया, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबाई गई। यह राज्य का दर्जा, हमारे अधिकारों, हमारी गरिमा और हमसे छिनी गई हर चीज के लिए हमारे संघर्ष की बस शुरुआत है। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नई दिल्ली के बाहरी-मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश के दौरान पार्टी नेताओं को पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी है और वे अपने संवैधानिक लक्ष्यों पर केंद्रित हैं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी ने ANI से बात करते हुए जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी से राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचता है और उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन मौजूदा अनिश्चितता को दूर करने के लिए है।

1109 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के कई ठिकानों पर छापेमारी

भुवनेश्वर। 1109 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा कदम उठाते हुए गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत से मिले तलाशी वारंट के आधार पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में कार्रवाई की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार, कंपनी पर बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय आंकड़ों और स्टॉक वैल्यू को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप है। जांच एजेंसी का कहना है कि कथित तौर पर गलत वित्तीय जानकारी के आधार पर ऋण सीमा बढ़वाई गई और बाद में ऋण राशि का दुरुपयोग करते हुए उसे अन्य खातों एवं उद्देश्यों में स्थानांतरित किया गया, जिससे बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर में कंपनी के चार निदेशकों के आवास, कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय, उत्तराखंड के काशीपुर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर तथा भुवनेश्वर स्थित उत्पादन इकाइयों की तलाशी ली गई। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की जांच जारी है और जल दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने विभिन्न बैंकों के कर्त्तव्यिभार से करीब 2900 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

» ब्लड पैरामीटर की बारीकी से विलनिकल निगरानी की जरूरत बनी हुई है

नई दिल्ली, एजेंसी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई सोमवार को सफ्दरगंज अस्पताल के अधिकारियों को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अस्पताल से कुछ देर के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगी है, ताकि वे कॉकरोच जनता पार्टी



(CJP) के संसद तक निकलने वाले 'संसद चलो' मार्च में शामिल हो सके। वांगचुक ने लिखा, 'मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत अच्छा

संसद घेरने चले कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, पुलिस से हुई तीखी झड़प



नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध मार्च को देखते हुए संसद परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्हें ऐसा करने के लिए एक NEE'T स्टूडेंट के पिता ने मनाया, जिसने आत्महत्या कर ली थी। सीजेपी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आत्महत्या करने वाली NEE'T स्टूडेंट रिया थापा के पिता ने अभिजीत दिपके को भूख हड़ताल खत्म करने के लिए मनाया, ताकि वे संसद तक मार्च का नेतृत्व कर सकें। संसद के मानसून सत्र के बीच इस बड़े आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। संसद भवन के कई गेट बंद कर किए गए हैं। सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव द्वारा X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध के दौरान संसद परिसर के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर

करने के लिए पुलिस ने कथित तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। संसद के मानसून सत्र और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रस्तावित विरोध मार्च को देखते हुए संसद परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया। खड़गे ने राज्यसभा में उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया था जो सीजेपी के संसद मार्च से पहले नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पार्टी के विरोध-प्रदर्शन स्थल पर जमा हुए थे। कॉकरोच जनता पार्टी (कांजपा) के संसद मार्च में सोमवार

को शामिल होने के लिए जंतर-मंतर जाने की कोशिश में कई प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री भवन के पास सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद सुरक्षा बलों ने खड़े हो। उन्होंने कहा कि पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है और उनकी पिटाई कर रही है। इसके साथ ही दास ने दावा किया कि 2 घंटे से ज्यादा ईंतजार करने के बाद, आशुतोष रांका और मैंने जेपी नड्डा जी से उनके घर पर 10 मिनट के लिए मुलाकात की। हमने अपनी मांगों के कारण कई यात्री मेट्रो स्टेशनों के अंदर ही फंसे रहे।

पेपर लीक- चढ़ावा चोरी पर लोकसभा में भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठकर सदन के मध्य भाग में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। कुछ सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए स्पीकर से हस्तक्षेप की अपील की। लगातार हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और नियमों के तहत अपनी बात रखने का आग्रह किया।

स्पीकर ने कहा कि संसद संवाद



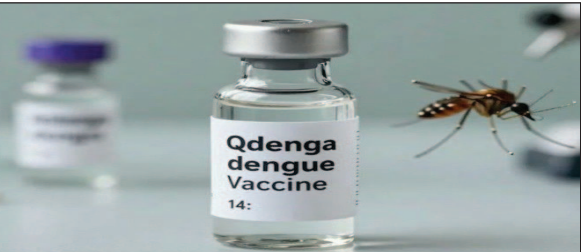
और सार्थक चर्चा का मंच है तथा सभी सदस्यों को नियमानुसार अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इससे संसदीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता है। शोर-शराबा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

उधर, राज्यसभा में भी विपक्ष ने

प्रदर्शनकारियों और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरौं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। उनके बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

डीसीजीआई ने ताकेदा की क्यूडेंगा को मंजूरी दी, भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन

मुंबई, एजेंसी। जापान की कंपनी ताकेदा Biopharmaceuticals ने सोमवार को घोषणा की कि भारत के ड्रग रेगुलेटर ने उसकी एंटी-डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मार्केट में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह देश में इस्तेमाल के लिए मंजूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया ने एक बयान में कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 4 से 60 साल की उम्र के लोगों में डेंगू की बीमारी से बचाव के लिए टाकेडा की डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' को मार्केट और क्लिनिकल ट्रायल (NDCIT) नियम, 2019) दे दिया है। कंपनी ने बताया कि क्यूडेंगा भारत में मंजूरी पाने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे उन



लोगों को भी दिया जा सकता है जिन्हें पहले डेंगू हुआ हो या नहीं हुआ हो, और इसके लिए वैक्सीन लगाने से पहले किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। भारत में डेंगू अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और हर साल इसके हजारों मामले सामने आते हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल फरवरी तक 6,927 मामले सामने आए और 10

लोगों की मौत हुई। यह बीमारी देश के ज्यादातर हिस्सों में फैली हुई है और दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों में से लगभग एक-तिहाई मामले यहीं से आते हैं। कंपनी के अनुसार, यह वैक्सीन डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप के खिलाफ असरदार है। टाकेडा में इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के हेड, महेंद्र नायक ने कहा कि क्यूडेंगा के सात साल के नए डेटा से पता चलता है कि यह सभी चार सीरोटाइप

डॉक्टरों की निगरानी में हैं वांगचुक

ये चिट्ठी सफ्दरगंज अस्पताल के अधिकारियों द्वारा भेजिए गए अपडेट में यह बताए जाने के कुछ समय बाद आई कि वांगचुक के जरूरी मेडिकल पैरामीटर स्थिर हैं, जबकि उनके ब्लड पैरामीटर की बारीकी से विलनिकल निगरानी की जरूरत बनी हुई है। ताजा हेल्थ बुलेटिन में कहा गया, “सोनम वांगचुक को VMMC और सफ्दरगंज अस्पताल में पूरी मेडिकल देखभाल मिल रही है। उनके जरूरी मेडिकल पैरामीटर स्थिर हैं। ब्लड पैरामीटर की बारीकी से विलनिकल निगरानी की जरूरत बनी हुई है। वांगचुक लगातार मेडिकल देखरेख और विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में हैं।” ये चिट्ठी वांगचुक के सरकारी अस्पताल में बने रहने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच भी आई है। उनकी पत्नी, गीताजलि जे आंग्मो ने आरोप लगाया है कि परिवार के सदस्यों को भी एक्टिविस्ट से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका दावा है कि उन्हें असल में पुलिस कस्टडी जैसी पाबंदियों के तहत रखा गया है।

महसूस कर रहा हूं और मेरी सेहत से जुड़े पैरामीटर भी बिल्कुल सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए, मैं आपसे

गुजारिश करता हूं कि मुझे अस्पताल से जाने की इजाजत दें, भले ही कुछ समय के लिए, ताकि मैं आज सुबह

संसद तक होने वाले मार्च, 'संसद चलो' में शामिल हो सकूँ।” उन्होंने आगे कहा, “मैं आपका बहुत आभारी

रहूंगा। ”

सोशल मीडिया पर लेटर शेयर करते हुए उन्होंने सवाल किया कि अगर पुलिस का कहना है कि एक्टिविस्ट को हिरासत में नहीं लिया गया है, तो उनके आने-जाने पर रोक क्यों लगाई गई है? उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक मैसेज में लिखा था, “सोनम वांगचुक आप सबसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल को एक लेटर दिया है क्योंकि उनकी सेहत ठीक है और उनका दावा है कि वो हिरासत में नहीं है। तो फिर रोक क्यों?”

छात्रों पर लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- यह सरकार नहीं, अहंकार है

नई दिल्ली, एजेंसी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को NEE-T-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने प्रशासन पर जन-कल्याण के बजाय अहंकार से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने छात्रों को हिरासत में लेने और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों को पुलिस स्टेशनों में रख रहे हैं और बाहर छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। यह कैसी सरकार है जो 'सबका साथ, सबका विकास' की बात तो करती है, लेकिन बच्चों की बात सुनना नहीं चाहती? क्या यह सरकार है या आपका अहंकार? अगर यह सरकार होती, तो बच्चों की बात सुनती। अखबार यादव ने नेशनल टेलिग्राफ एजेंसी की ईमानदारी और राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर NEE'T परीक्षा हुई और उसमें नकल हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विश्वसनीयता का क्या? इसकी तैयारी किसे करनी थी?

जहां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि हां तथ्य और तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत हैं और तर्क मजबूत हैं तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। हर आवाज को अवसर मिले और हर विचार को सम्मान मिले, यह संसद की हमारी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी सांसदों से बड़-चढ़कर सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आज सुबह लोकसभा स्पीकर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सांसदों का स्वागत करने के अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाता हूं।



और जान की देश व संसद को जरूरत है। आज के लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना और मिल-जुलकर देश को आगे ले जाने का संकल्प लेना, मैं समझता हूं कि यह समय की मांग की है। पीएम मोदी ने आगे कहा,

एक्सप्रेसन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़ें। आज समय की मांग है कि राष्ट्रनिष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रही आवाज, को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे आवाज को बुलंद करें और देश को दिशा दें।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी : सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई, एसआईटी के पुनर्गठन का दिया आदेश

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं से मिले दान में कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अदालत ने साफ संकेत दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पुनर्गठन पर आवश्यक निर्देश देने को कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जांच अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ अयोध्या राम मंदिर में मिले दान के कथित गबन की सीबीआई



जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी से जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत ने साफ संकेत दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पुनर्गठन पर आवश्यक निर्देश देने को कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जांच अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ अयोध्या राम मंदिर में मिले दान के कथित गबन की सीबीआई

गुमशुदगी से हत्या तक : 12 दिन
बाद खुला अमित हत्याकांड, चार के
खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

तूतना ही नहीं, विविध करने पर उन्हें
 भी जान से मारने की धमकी दी गई।
 बताया जाता है कि अमित कुमार को
 मुम्बई-मुम्बई 7 जुलाई 2026 को दर्ज
 कराई गई थी। इसके दो दिन बाद 9
 जुलाई को कूरेशी क्षेत्र स्थित शाददा
 नहर के फाटक में उसकी लाश फंसी
 मिली थी। शिव मिलने के बाद से
 परिजन हत्या की आशंका जता रहे
 थे। वादी की तहरीर के आधार पर
 धनपतगंज पुलिस ने मु.अ.सं.
 0133/2026 के तहत धारा
 103(1) एवं 351(3) बीएनएस में
 मुम्बई दर्ज किया है। मामले में
 संगीता पुत्री मीहिला, लक्ष्मी पुत्री
 मीहिला निवासी ग्राम एकलखी
 थाना धनपतगंज, रामवरन तथा
 शशिकान्त पुत्र खुंदी निवासी ग्राम
 सेवरा को नामजद आरोपी बनाया
 गया है।

डायरिया रोको अभियान का शुभारम्भ, घर-घर पहुंचाएंगे डायरिया से बचाव के संदेश

इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुज चौधरी, जिला मातृ स्वास्थ्य सलाहकार मुकेश गौतम, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक विवेक सारस्वत, बीसीटीपीएम अजय कुमार, पीएसआईआईडिया से कोमल शर्मा, अजय कुमार, डॉ. बसु सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

हमौरपुर में दादी को कुल्हाड़ी से काटने वाले हत्यारे पोते का कबूलनामा



अतर सिंह और उनकी पत्नी अनिता की मौत से गांव का हर कोई व्यक्ति स्तब्ध है। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। अतर सिंह और अनिता का पूरा परिवार है। इसके बावजूद दोनों का इतना बड़ा कदम उठाना लोगों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पति-पत्नी के बीच गहरा स्नेह था और वह अधिकांश समय साथ ही रहते थे। अतर सिंह ही मेमसा अपनी बीमार पत्नी को दवाई दिलवाने जाते थे। यह समझा से जेप है कि दोनों ने एक साथ अपनी जीवन्तलीला समाप्त करने का कठोर निर्णय लिया।

जानकारी के मुताबिक, पखलाली गांव निवासी सुरेश कुमार के सुलतानपुर डाकघर में 10 आरडी खाते संचालित हैं। निजी आवस्यकता के चलते सोमवार को वह समय से पूर्व भुगतान के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर काउंटर सहायक पवन कुमार के पास पहुंचे। आरोप है कि भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध करते ही कर्मचारी का व्यवहार बदल गया और उन्होंने उपभोक्ता के साथथाना अग्रदूत भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया।

परमाणु संयंत्र का डाटा लीक हो गया, क्या ऐसी साइबर सुरक्षा के भरोसे आगे बढ़ेगा डिजिटल इंडिया?

देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हजारों गोपनीय दस्तावेज लेकर रूप से सार्वजनिक होने के बाद भारत की महत्वपूर्ण अवसरचतना की साइबर सुरक्षा को कथित रूप से गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। हम आपको बता दें कि नैसमन्तवेयर गिरोर एड्स लूकशर ने दावा किया है कि उसने संयंत्र से संबंधित 19 हजार से अधिक संवेदनशील फाइलें डार्क वेब पर जारी कर दी हैं। इन दस्तावेजों को लगभग 8 लाख 58 हजार फाइलों के उस बड़े संग्रह का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे परियोजना से जुड़े ठेकेदार रिलायंस समूह के डाटा से चुराया गया है। हालांकि इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, फिर भी विशेषज्ञ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर मामला मान रहे हैं।

इस बीच, रिलायंस समूह ने मॉडिया की बताया कि तीसरे पक्ष के भारतीय डाटा सेंटर प्रदाता योद्धा के संवर पर सख्त गए उसके डाटा में ऑसिक संसंधारी हुई है। कंपनी के अनुसार इसका को इस घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन कस प्रकर डाटा प्रामित्य हुआ, सरका खुलासा नहीं किया गया। दूसरी ओर योद्धा ने कहा कि उसने 29 मई को संवर पर संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा लिया था और संदिग्ध रिलयंसमेवर की संसंधारी होने से रोका दिया गया था। बाद में रिलयंस इम्फ्रस्ट्रक्चर ने संभावित डाटा लीक के दावे की जानकारी दी। कंप्यूटरसिद्धान्त हम आपको बता दें कि कथित रूप से लोक हुए दस्तावेज वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2025 के मध्य तक के बताए जा रहे हैं। इन्में वॉट्सएप और शोतनम प्रामाणियों के ईमेलनियरिग नक्शे, साक्षा नियंत्रण कक्ष की रूपरेखा, उपकरणों के निरीक्षण प्रतिवेदन, आपूर्तिकर्ताओं की सूची, विक्रेताओं के प्रस्ताव, बैठकों के अभिलेख तथा बीमा संबंधी दस्तावेज शामिल बताए गए हैं। अधिकोश दस्तावेज कुडनकुलम परियोजना की तीसरी और चौथी इकाई से संबंधित हैं, जिनका निर्माण कार्य जारी है और जिनके वर्ष 2027 तक चालू होने की संभावना है। राहत की बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमें परमाणु रिफ़क्टर के मुख्य तंत्र की रूपरेखा शामिल नहीं है, क्योंकि वह रूस की सरकारी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

फिर भी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी जानकारी शतावधिपूर्ण तत्वों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी हमलावर को यह जानकारी मिल जाए कि परियोजना में किन व्यक्तियों, ठेकेदारों और प्रणालियों की पहुंच कहां तक है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से परमाणु रिएक्टर पर हमला किए बिना भी उससे जुड़ी सहायक व्यवस्थाओं, संगठित श्रृंखला या तीसरे पक्ष की प्रणालियों को निशाना बना सकता है। इससे परियोजना के अप्रत्यांत, खराब और सुरक्षा व्यवस्था पर अप्रत्यक्ष खराब उत्पन्न हो सकता है।

इस पूरे मामले को जांच भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि संयंत्र की परिचालन णणाली या परमाणु रिएक्टर की सुरक्षा से सीधे सम्बन्धित हुआ है। परमाणु ऊर्जा विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि संबंधित हैकर गिरोह पहले भी कई प्रमुख औद्योगिक संस्थानों को निशाना बना चुका है। देखा जाये तो यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में लगभग दो करोड़ नवारी लाख खाते किसी न किसी रूप में डाटा समझौते का शिकार हुए, जिससे भारत विश्व के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा। वहीं हाल के एक औद्योगिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 73 प्रतिशत भारतीय संस्थानों को यह तक जानकारी नहीं थी कि वे कौन साइबर हमले का शिकार हुए हैं या नहीं, जबकि 57 प्रतिशत संस्थानों में बुनियादी साइबर उपायों का भी अभाव है।

देखा जाये तो कुड़नकुड़न परमाणु ऊर्जा परियोजना केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु क्षमता और सामरिक अतिरिक्तभारत का महत्वपूर्ण आधार भी है। इस परियोजना पर किसी भी प्रकार का साइबर हमला या गोपनीय सूचनाओं का लीक होना सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आधुनिक युद्ध में साइबर क्षेत्र को भूमि, जल, वायु और अंतरिक्ष के समान ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण अवसंरचना से संबंधित सूचनाओं का दुरुपयोग कर शत्रु देश या संगठित साइबर अपराधी बिना प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के भी रणनीतिक दबाव बना सकते हैं।

त्यंग्य

समूल सुधार की जरूरत



नीट-यूजी, जेईई, सीयूईटी आदि जैसी परीक्षाओं का मौजूदा ढांचा कोई संयोगवश सामने नहीं आया है। यह नीतिगत प्राथमिकताओं का परिणाम है। पूर्व चेतावनियों के बावजूद केंद्र ने इन्हें विभिन्न स्तरों पर लागू किया है।

पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को अनवरत घटनाओं से बढ़ते युवा असंतोष के बीच शिक्षा मंत्रालय को नौ सदस्यीय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कोचिंग संस्थानों का दबदबा तमाम बुराइयों का मूल कारण है। कमेटी के मुताबिक इन संस्थानों को विनियमित करने की जरूरत है, लेकिन यह सिर्फ औचक निरीक्षण या गुमराह करने वाले इशतहारों पर रोक लगा कर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने और नीट-पूजी, जेईई, और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं का डिजाइन बदलने की जरूरत होगी। डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जिससे छात्रों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता घटे।

जून 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा संचयन विनियमों का अंशभूतता में य
कमेटी बनाई थी। मकरद कोचिंग संस्थानों के 'डमी स्कूलों' बन जाने की समस्या से निजात
और प्रवेश परीक्षाओं की स्वच्छता सुनिश्चित करने के बारे में सुझाव देना था। मीडिया रिपोर्टों
के मुताबिक कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर दी। संभवतः दो हफ्तों में वह ऑनलाइन
रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। मगर ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में सामने आई जानकारीयें से नहीं लगता
कि समिति समस्या की जड़ तक पहुंचेगी है। नीट, जेईई, सीयूईटी की परीक्षाओं का मौजूदा ढांचा
कोई संयोगवश सामने नहीं आया है। यह नीतिगत प्रार्थमिकताओं का परिणाम है। सीयूईटी की
प्रस्ताव जब आया, तो चेतावनी दी गई थी कि इससे स्कूली पढ़ाई का महत्व घटेगा और कोचिंग
संस्थानों का धंधा बढ़ेगा।

फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कॉलेजों में दाखिले के लिए ये नया सिस्टम लागू किया। और फिर समस्या सिर्फ इलीट परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लौक हो गया। परीक्षा आयोजन में ऐसी गड़बड़यियाँ देश भर में आ जाड़ तक पहुँच चुकी हैं। उनके रहते ऊपरी परीक्षाओं को दोषमूलक बना लिया जाएगा, यह सोच अपने-आप में समस्याग्रस्त है। अतः जोशी कमेटी की रिफारिशों से मीडिया और आम चर्चाओं को फौरी तौर पर नमैन करने में भले कुछ कामयाबी मिल जाए, उनसे ध्वस्त होती परीक्षा व्यवस्था नहीं संभलेगी। उसके लिए जिस समग्र और समूल सुधार की जरूरत है, वह फिलहाल सरकार की सोच से बाहर है।

मंदिरों में भ्रष्टाचार: वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो

ललित गर्ग

भारत की पहचान केवल उसी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है, बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी, तिरुपति, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, सालासपर बालाजी, खडूट ध्यानगौरी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति, पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं, तब केवल कोई संस्था बदनাম नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है। हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर, बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है। मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है-वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई-कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, विद्यार्थी और छोटे बच्चों के साथ आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है, सामान्य दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं। यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का

दर्शन होगा तो यह धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बनाया चाहिए, न कि सामंजस्य असमानता का मंच। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में 'समान मन्दिर दर्शन नीति' लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो, तब भी आम श्रद्धालुओं को दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए, पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की चढ़ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है, फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान-पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, बारकोड आधारित सीलिंग, निगमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय-व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके दान दिया गया कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है।

इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक प्रहचान ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्पत्तक हो, जिनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा हो और जिन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप न हों। समय-समय पर उनके कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। मंदिर प्रबंधन किसी का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। मुंदिरों में सेवा करने वाले पुजारीयों, कर्मचारियों के सुरुक्षा कर्मियों के लिए भी अपार-संहिता बनाई जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र प्रवृत्त, दलालों से मिलीभगत, नशाखोरी या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो। सालासर बालाजी में बारंसेरों द्वारा श्रद्धालु की पिटाई और खाटू श्यामजी में मुख्य पुजारी से जुड़े विवाद जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि केवल धार्मिक प्रहचान पर्याप्त नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है।

ब्लॉग

बांकीपुर उपचुनाव 2026: भाजपा उम्मीदवार के यकायक बदलाव से उभरने लगे सुलगते सवाल?

कमलेश पांडे जानकारी से उभरी चिंताएं: कुछ मीडिया रिपोर्टों में

भोजपुरी में एक कहावत है- लड़का मालिक, बूढ़ा दीवान, मामला बिगड़े सँझ बिहात। यानी कि जिस घर का मालिक होता है और बूढ़ा व्यक्ति दीवान मतलब सलहकार की भूमिका में आ जाता है तो वहां अच्छे और कार्यकुशल सुझावों पर भी विलंब से निर्णय होने के चलते मामला सँझ यानी शाम से सुबह तक कभी भी उलझ यानी बिगड़ जाता है। यदि भोजपुरी कुछ बातों को भूला भी दिया जाता तो हाल ही में बाँकपुर उपचुनाव में भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) का नामांकन वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्तिन नबीन को काफी किरकरी हुई है।

चूँकि उनका चयन प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पर यकायक हुआ है, इसलिए उँगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी उठी। बात इतनी सी नहीं है, बल्कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उनके चेहेते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सियासी रणनीति भी अचानक सवाल के घेरे में आ गई। यही वजह है कि

मई दिराली से लेकर पाटलिपुत्र/पटना के सिपायों गलियारों में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोग एक दूसरे से यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर बाँकीपुर उपचुनाव की उड़ाचढ़ में हुए रज्जूमोदीवार बदलने के निर्णायक निर्णय में किसका प्रभुत्व भारी रहा- प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गूधमत्री का ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा और बिहार के मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी का। प्रचारअभियान और चुनाव

यह प्रश्न है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को अपने ही घोषित उम्मीदवार को बदलने की को नौबत क्यों आई? क्या यह राष्ट्रीय अर्थसूची और प्रदेश अर्थसूची की विफलता नहीं है? क्या यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या दोनों की गमुराह करके बदनाम करने की कोई नई चाल तो नहीं है? या फिर बुध और बात है, एक तहकीकात तो बनी ही है, ताकि भविष्य में ऐसे फैसलों से बचा जा सके। वाकई बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा द्वारा पहले अभिषेक कुमार (बंदी) को उम्मीदवार बनाया और फिर उनका नाम वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित करना आधिकारिक रूप से किसे सवाल खड़े करता है। आधिकारिक तौर पर अभिषेक कुमार ने 'परावारिक कारणों' का हवाला देकर नामांकन वापस लिया है।

हालांकि राजनीतिक हलकों और मीडिया चर्चाओं में कुछ संभावित कारणों की चर्चा है, जिन्हें केवल अवलोकन या विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए। चूंकि राष्ट्रीय व सुबाई मीडिया के राजनीतिक विश्लेषण में कुछ संभावित पहलुओं पर चर्चा हो रही है तो लाजमी है और इसप्रकार से है- पहली, उम्मीदवार की पष्ठभूमि पर मिली नई

जानकारी से उभरी चिंगाएँ: कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उम्मीदवार से जुड़े एक संभावित विवाद की जानकारी नामांकन के बाद सामने आने पर पार्टी ने जोखिम लेने के बजाय उम्मीदवार बदलना ही बेहतर समझा। चूंकि नामांकन के बाद कुछ ऐसी सूचनाएँ सामने आईं जिन्हें पार्टी चुनावी दृष्टि से जोखिमपूर्ण मान रही थी। हालाँकि इस पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

दूसरी, स्थानीय संगठन की असहमति: कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पटना महानगर और बांकीपुर के स्थानीय नेताओं का एक वर्ग घोषित उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह सहज नहीं था। यदि ऐसा था, तो चुनाव प्रबंधन प्रभावित होने की आशंका रही होगी। राजनीति

तीसरी, जीत की संभावना : भाजपा बांकीपुर को अपनी परंपरागत मजबूत सीट मानती है। यदि आंतरिक सर्वे या फीडबैक में उम्मीदवार को लेकर नकारात्मक संकेत मिले हों, तो अंतिम समय में बदलाव को बेहतर विकल्प माना गया होगा।

चौथी, विपक्ष को मुद्दा बनने से रोकना: यदि पार्टी को लगा कि उम्मीदवार से जुड़ा कोई विवाद चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो उसने पहले ही उम्मीदवार बदलकर संभावित नुकसान कम करने की कोशिश की हो सकती है।

पाचवा, क्या यह नेतृत्व की विफलता है? : इसके दो पक्ष हैं—यदि उम्मीदवार की पूरी जांच के बाद ही नाम घोषित हुआ था और बाद में वही कारण बदलने की वजह बना, तो प्रारंभिक जांच प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

लेकिन यदि नामांकन के बाद कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, तो उम्मीदवार बदलना संगठन की त्वरित प्रतिक्रिया भी माना जा सकता है।

छठी, क्या यह संगठन की विफलता है? : यदि किसी उम्मीदवार को केंद्रीय चुनाव समिति तक मंजूरी मिलने के बाद बदलना पड़े, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रारंभिक जांच (due diligence) पूरी तरह हुई थी या नहीं। इस दृष्टि से आलोचक इसे संकटनात्मक कमी मान सकते हैं। या फिर यह नुकसान सीमित करने की रणनीति थी?

सातवीं, नुकसान नियंत्रित (damage control) करने की रणनीति : यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि नामांकन के बाद कोई नई जानकारी सामने आए और पार्टी तुरंत निर्णय लेकर उम्मीदवार बदल दे, तो इसे नुकसान नियंत्रित करने की रणनीति भी माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में बाद में बड़ा विवाद झेलने की बजाय तत्काल निर्णय लेना नेतृत्व की सक्रियता भी माना जा सकता है।

आठवीं, सबकछ सामान्य है या असामान्य,

चिता की बात: यहाँ यह कहना कि यह केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष की विफलता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अभी जल्दबाजी होगी। वहीं यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सब कुछ सामान्य था। दोनों संभावनाओं के बीच सच्चाई इस बात पर निर्भर करेगी कि उम्मीदवार बदलने की वास्तविक वजह क्या थी, जिसे भाजपा ने सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताया है।

नावाँ, संगठनात्मक जवाबदेही का यश्र प्रश्न। ऐसे में यदि भविष्य में यह स्पष्ट हो जाए कि विवादित जानकारी पहले से उपलब्ध थी और जांच में चूक हुई, तो संगठनात्मक जवाबदेही का प्रश्न अधिक मजबूती से उठेगा। लेकिन यदि जानकारी बाद में सामने आए और उस आधार पर निर्णय लिया गया, तो इसे व्यक्तिगत जेखिम प्रबंधन के रूप में भी देखा जा सकता है।

दसवीं, भाजपा ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी, इसलिए सबकुछ भविष्य पर निर्भर: जूना बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बदलने के पीछे के 'अंदरूनी कारणों' पर अभी तक भाजपा ने कोशिश आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसलिए किसी एक कारण को तथ्य के रूप में कहना उचित नहीं होगा।

हालाँकि इस समय उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उम्मीदवार परिवर्तन का वास्तविक कारण क्या था इसलिए किसी विशेष व्यक्ति, गुट या नेतृत्व पर निश्चित आरोप लगाना तथ्यों से परे होगा। यदि भविष्य में आधिकारिक दस्तावेज़, विध्वंसनीय रिपोर्ट या संबंधित पक्षों के बयान सामने आते हैं, तब अधिक ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

आखिर राजनीति के अंतःपुर में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, किस खेमे में कौन सी सुस्वादु खिचड़ी पक रही है, यह अंदाजा भी आपको होना चाहिए

वहीं, एक अन्य चोपाली चर्चा के मुताबिक बाजपा का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बाजपा के बिहार की बस में आने के बाद से पहले मुख्यमंत्री बदल यानी नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी का राज्याभिषेक और अब बांकीपुर उन्मुचनाव में उम्मीदवार बदल यानी बाजपा द्वारा पूर्व में घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) का नामांकन वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने की सामान्य घटनाक्रम नहीं उद्घारया जा सकता है। यह बिहार एनटीए के आपसी दौंवसेच के भी अभिप्रेत ही सकता है। चूँकि बिहार के कद्वर नेता इन दिनों हाशिए पर चले गए हैं, इसलिये वो नहीं चाहते कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे सुलहे लुहे नेता सफल हों, क्योंकि इनकी सफलता से उनका सिपायसी भविष्य उलझ जाएगा।

मंदिरों में दलाल संस्कृति भी समाप्त की जानी चाहिए। दर्शन, प्रयाद, पूजा और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर होने वाली अर्न्तकृत वसूली श्रद्धालुओं के विश्वास को कमजोर करती है। सभी सेवाओं की दृष्टि से सार्वजनिक हों, ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध हो और किसी भी अतिरिक्त वसूली पर कठोर दंड का प्रावधान हो। भारत आर्य विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया भर से करोड़ों लोग भारत में मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। ऐसे समय यदि मंदिरों की व्यवस्थाओं पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अव्यवस्था के आरोप लगाते हैं तो केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की छवि प्रभावित होती है। विश्व यह संदेश ग्रहण करता है कि जिस देश ने धर्म और नैतिकता का संदेश दिया, वह अपने ही धर्मस्थलों को पारदर्शी नहीं बना पाया, वह अपने ही व्यापक भ्रष्टाचार परसरा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को अब इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया जा सकता है, जो बड़े मंदिरों की वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही, दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं के अधिकारों की निगरानी करे। प्रत्येक मंदिर के लिए सेवा-मानक निर्धारित हों तथा शिकायत निवारण की समग्रबद्ध व्यवस्था हो। धार्मिक संतानों और संत समाज को भी आत्मबंधन करना होगा। धर्म की अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि सेवा, ईमानदारी, सेवा और उत्तरदायित्व है। यदि मंदिरों के भीतर ही इस मूल्यों का ह्रास होगा तो समाज को नैतिक दिशा की क्या दिशा? मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के विद्यालय भी होने चाहिए। आज आवश्यकता किसी छोटे-मोटे सुधार की नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन में एक नैतिक क्रांति की है। यह क्रांति पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और सेवा के चार स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। मंदिरों की तकनीकी से जोड़ना होगा, वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और ऑडिट-आधारित बनाना होगा, वही आईपी संस्कृति को समाप्त करता होगा तथा हम श्रद्धालु को समान समाप्त देना होगा। याद रखना होगा कि मंदिरों की सबसे बड़ी संपत्ति उनका स्वर्ण, रतन या चढ़ावा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया तो सबसे बड़ा मंदिर भी अपनी आत्मा खो देगा।

टैक्सपेयर्स ध्यान दें! आईटीआर फॉर्म में आया नया कॉलम, क्यों आपका दूसरा अड्रेस जानना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

IT एक्ट में असेसमेंट ईयर 2026-27 के आईटीआर के मकसद से ‘करंट’, ‘परमानेंट’ और ‘सेकेंडरी’ पतों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। आईटीआर फॉर्म में मुख्य रूप से प्राइमरी पते और सेकेंडरी पते का जिक्र कम्युनिकेशन के मकसद से किए जाने वाले पतों के तौर पर किया गया है।



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर की प्रोफाइलिंग बेहतर करने, बातचीत को आसान बनाने और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में डेटा की सटीकता बढ़ाने की अपनी बड़ी पहल के तहत, असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में एक जरूरी ‘सेकेंडरी एड्रेस’ (दूसरा पता) फील्ड शामिल किया है।

इन नए फील्ड को आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक सभी आईटीआर फॉर्म में जोड़ा गया है। इसमें सैलरीड लोग, प्रोफेशनल्स, बिजनेस, फर्म, LLP, कंपनियां, ट्रस्ट और इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले अन्य तरह के टैक्सपेयर शामिल हैं। ऐसा लगता है कि यह कदम आईटीआर फॉर्म में टैक्सपेयर की ज्यादा पूरी और व्यवस्थित जानकारी हासिल करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

इससे डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट और अड्रेस की जानकारी अपडेट रखने, बातचीत में कमी (गैप) को कम करने और बेहतर वैरिफिकेशन में मदद मिल सकती है। यह तब खास तौर पर मददगार होगा जब किसी टैक्सपेयर के पास एक से ज्यादा जरूरी अड्रेस हों, जैसे कि परमानेंट अड्रेस, करंट अड्रेस, काम करने की जगह या फाइनैशियल/टैक्स रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अड्रेस।

हालाँकि, टैक्सपेयर को यह पक्का करना चाहिए कि बताया गया सेकेंडरी एड्रेस सही हो और उनके रिकॉर्ड से मेल खाता हो। अगर सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस (मुख्य पता) एक ही हैं, तो टैक्सपेयर बिना वजह अलग जानकारी देने के बजाय

यूटिलिटी में वही जानकारी दे सकता है।

किन आईटीआर फॉर्म में यह नया फ़ील्ड है?

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए, नोटिफाई किए गए आईटीआर फॉर्म के ‘पार्ट A जनरल / पर्सनल इन्फॉर्मेशन’ में सेकेंडरी एड्रेस फील्ड जोड़ा गया है। इसमें आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-5, आईटीआर-6 और आईटीआर-7 शामिल हैं, क्योंकि नोटिफाई किए गए फ़ॉर्म में अब बातचीत के लिए प्राइमरी

एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस के लिए अलग-अलग फील्ड दिए गए हैं।

सेकेंडरी एड्रेस असल में क्या होता है?

सेकेंडरी एड्रेस में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बताए गए प्राइमरी एड्रेस के अलावा, टैक्सपेयर से जुड़ा कोई भी अतिरिक्त मान्य फिजिकल पता शामिल हो सकता है। यह ऐसी जगह हो सकती है जहां टैक्सपेयर रहता हो, काम करता हो, बिजनेस करता हो या ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त करता हो। सीए (डॉ।) सुरेश सुराना ने एफई की रिपोर्ट में कहा कि इनकम-टैक्स एक्ट में ‘सेकेंडरी एड्रेस’ की कोई अलग विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई है। हालाँकि, इसका मकसद बातचीत के लिए एक वैकल्पिक पता हासिल करना है, जैसे कि मौजूदा घर का पता, परमानेंट पता, ऑफिस/रजिस्टर्ड पता या प्राइमरी एड्रेस से अलग कोई अन्य जरूरी पता। अगर टैक्सपेयर का कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही पता है, तो वे बता सकते हैं कि सेकेंडरी पता, प्राइमरी पते जैसा ही है। अगर यह अलग है, तो अलग सेकेंडरी पता सही-सही बताना चाहिए।

विभाग करंट, परमानेंट और सेकेंडरी एड्रेस को कैसे डिफाइन करता है?

IT एक्ट में असेसमेंट ईयर 2026-27 के आईटीआर के मकसद से “करंट”, “परमानेंट” और “सेकेंडरी” पतों को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। आईटीआर फॉर्म में मुख्य रूप से प्राइमरी पते और सेकेंडरी पते का जिक्र कम्युनिकेशन के

मकसद से किए जाने वाले पतों के तौर पर किया गया है। व्यावहारिक तौर पर, करंट एड्रेस का मतलब वह जगह हो सकती है जहां टैक्सपेयर का रिटर्न फाइल करते समय रहने या बिजनेस का मौजूदा या मुख्य स्थान हो, जिसका इस्तेमाल मुख्य कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा।

सुराना ने कहा कि परमानेंट एड्रेस का मतलब लंबे समय तक रहने वाली या पेतुक जगह से हो सकता है जो अस्थायी रूप से कहीं और रहने के बावजूद टैक्सपेयर से जुड़ी रहती है। वहीं, सेकेंडरी पते में इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बताए गए प्राइमरी पते के अलावा टैक्सपेयर से जुड़ा कोई भी अतिरिक्त मान्य फिजिकल एड्रेस शामिल हो सकता है।

अगर आधार या पैन रिकॉर्ड में सेकेंडरी एड्रेस अपडेट नहीं तो...

सिर्फ इसलिए कि आईटीआर में दिया गया सेकेंडरी एड्रेस आधार या पैन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, मिसमैच होने से अपने आप कंप्लायंस से जुड़ी समस्या नहीं होगी। सुराना ने कहा कि हालाँकि, टैक्सपेयर्स को यह पक्का करना चाहिए कि बताया गया पता सही और असली हो। चूंकि आईटीआर की जानकारी को पैन, आधार, बैंक, एम्प्लॉयर और दूसरे रिकॉर्ड से क्रॉस-वैरिफाई किया जा सकता है, इसलिए बड़ी गड़बड़ियों से वैरिफिकेशन या कंप्यूनिकेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, जहां पते में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, वहां जरूरी रिकॉर्ड को अपडेट रखना सही रहता है।

क्या टैक्सपेयर्स रिवाइज्ड आईटीआर के जरिए सेकेंडरी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं?

सुराना के अनुसार, अगर किसी टैक्सपेयर को पता चलता है कि ऑरिजिनल रिटर्न में बताया गया सेकेंडरी एड्रेस गलत या अधूरा है, या उसमें बदलाव हुआ है, तो तय समय सीमा के अंदर सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके जानकारी को आमतौर पर ठीक किया जा सकता है। शर्त यह है कि ऑरिजिनल रिटर्न तय तारीख के अंदर फाइल किया गया हो।

रिवाइज्ड रिटर्न टैक्सपेयर्स को गलतियों और कमियों को ठीक करने की सुविधा देता है, जिसमें आईटीआर में बताई गई पर्सनल और कॉन्टेक्ट जानकारी भी शामिल है। हालाँकि, अगर बदलाव सिर्फ प्यूचर कंप्यूनिकेशन के लिए है, तो टैक्सपेयर्स अपने ई-फाइलिंग प्रोफाइल में भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।

गेहूं एक महीने में 8 फीसदी महंगा, बढ़ सकती हैं खाद्य तेल की कीमतें, क्यों बिगड़ रहा रसोई का बजट ?



नई दिल्ली, एजेंसी। त्योहारी सीजन से ठीक पहले रसोई का बजट फिर बिगड़ सकता है। घरेलू बाजार में पिछले एक माह में गेहूं की कीमतें 8 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी आने की पूरी आशंका है।

काले सागर में आपूर्ति के बढ़ते जोखिमों के कारण शिकागो गेहूं वायदा पिछले सत्र में 5 फीसदी उछलने के बाद दो महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया है। यूक्रेन के बंदरगाह पर हुए हमलों से गेहूं निर्यात प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर, अजोब सागर और केच जलडमरूमध्य में प्रतिबंध से रूस का गेहूं निर्यात भी मुश्किल में आ गया है। इन व्यवधानों ने वैश्विक गेहूं बाजारों में एक जोखिम प्रीमियम जोड़ दिया है।

गेहूं की वैश्विक कीमतों में आए इस उछाल का असर भारतीय बाजार पर भी हुआ है। इस दौरान इंदौर मंडी में गेहूं के दाम सबसे अधिक 8.44 फीसदी तक बढ़े हैं। दिल्ली, कानपुर और कोटा जैसी प्रमुख मंडियों में कीमतें औसतन 3.5-4 फीसदी के बीच बढ़ी हैं।

गेहूं उत्पादन हो सकता है प्रभावित

गेहूं उत्पादन का परिदृश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि बढ़ता तापमान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पैदावार एवं अनाज की गुणवत्ता के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। मौसम में हालिया व्यवधानों के कारण व्यापारियों ने अगले रबी सीजन के उत्पादन पूर्वानुमान को 11.35 करोड़ टन से घटाकर 11.40 करोड़ टन कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन के बावजूद शुरुआती उम्मीदों से कम है।

खाद्य तेलों में तेजी के चार कारण

इस साल सोयाबीन की खेती 6 फीसदी तक कम रहने की आशंका है। 15 दिनों में बारिश में सुधार नहीं हुआ, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी 5 से 7 फीसदी घट सकता है।

वैश्विक बाजारों में पाम तेल की उपलब्धता में कमी और घरेलू बाजार में सरसों व सोयाबीन के पर्याप्त स्टॉक के चलते भारत ने आयात कम किया है, जिससे आने वाले समय में घरेलू स्टॉक पर दबाव बढ़ेगा।

एफएमसीजी कंपनियों और स्टॉकिस्टों की मांग थोड़ी सुस्त जरूर है। लेकिन, अगरस्त के पहले पखवाड़े से बाजार में रिकवरी आएगी और दिवाली तक त्योहारी मांग चरम पर होगी। यह मांग कीमतों को और ऊपर धकेलेगी।

वैश्विक स्तर पर बायोफ्यूल में पाम तेल का इस्तेमाल बढ़ने से सोया तेल और सूरजमुखी तेल महंगा हुआ है। रुपये की कमजोरी ने रिफाइनर्स के लिए आयात लागत बढ़ा दिया है।

कितने बढ़ सकते हैं खाद्य तेल के दाम?

विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में अचानक कोई बड़ा विस्फोट भले न हो, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में तेजी बनी रहेगी। सूरजमुखी तेल 1,580 से 1,600 प्रति क्विंटल के स्तर पर बनी रहेगी। यानी इसके दाम 160 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बने रहने के आसार हैं। सोयाबीन तेल का दाम 1,420 रुपये के मजबूत स्तर पर बरकरार रहने की उम्मीद है, जिससे इसमें मंदी की गुंजाइश खत्म हो गई है। पाम तेल काफी अच्छे डिस्काउंट पर आ चुका है, इसलिए 1,340 से 1,350 के स्तर पर इसमें तगड़ी खरीदारी लौटती दिख रही है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चौथी बार बने पिता, पत्नी उषा ने दिया बेटे को जन्म, 156 साल बाद बना अनोखा रिकॉर्ड

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस के घर चौथी संतान का जन्म हुआ है। दोनों ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके बेटे का जन्म हुआ है। बच्चे का नाम एलेक नील वेंस रखा गया है। इसके साथ ही जेडी वेंस 156 साल से ज्यादा समय बाद पद पर रहते हुए पिता बनने वाले पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एलेक नील वेंस, जेडी और उषा वेंस की चौथी संतान हैं। इससे पहले उनके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे इवान की उम्र 9 साल, दूसरे बेटे विवेक की उम्र 6 साल और बेटी मिराबेल की उम्र 4 साल है। जेडी वेंस और उषा वेंस ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज सुबह हमारे बेटे एलेक नील वेंस का जन्म हुआ है। उषा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हमारे तीनों बच्चे भी अपने छोटे भाई के आने से बेहद खुश हैं। दंपति ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों,

नर्सों और पूरे मेडिकल स्टाफ के साथ-साथ व्हाइट हाउस की मेडिकल टीम का भी धन्यवाद किया। 41 वर्षीय जेडी वेंस लंबे समय से अमेरिका में घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। उन्होंने 2021 में ओहायो से सीनेट चुनाव लड़ते समय भी इस मुद्दे को उठाया था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद 2025 में आयोजित मार्च फॉर लाइफ कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका में ज्यादा बच्चे पैदा हों। वेंस ने यह भी बताया था कि उनके करीबी दोस्त चार्ली किर्क की 2025 में हुई हत्या ने उन्हें एक और बच्चा पैदा करने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। जेडी वेंस पहले अमेरिकी मरीन में रह चुके हैं। विदेश दौरो पर उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे भी कई बार उनके साथ गए हैं। रात की लंबी उड़ानों के दौरान बच्चों को कई बार एयर फोर्स टूट में पायजामा पहनकर चढ़ते हुए भी देखा गया है। 40 साल की उषा वेंस भारतीय मूल के प्रवासी माता-पिता की बेटी हैं।

जनवरी में जब उनकी प्रेनेंसी की घोषणा हुई थी, तभी से वह चर्चा में थीं। अमेरिका में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर रहते हुए परिवार में नए बच्चे का जन्म होना बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पहले 1870 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति शायलर कोलफैक्स के कार्यकाल के दौरान उनके बेटे शायलर कोलफैक्स तृतीय का जन्म हुआ था। उससे पहले 1829 में उपराष्ट्रपति जॉन सी कैलहून के बेटे विलियम का जन्म हुआ था। यह जानकारी व्हाइट हाउस हिस्टोरिकल एसोसिएशन ने दी है। अंदर मौजूद तेल ठिकानों पर यूक्रेन के हमलों को रोकना चाहता है, क्योंकि इन हमलों से ईंधन की भारी कमी हो गई है, जिससे सेना और आम नागरिक दोनों प्रभावित हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं। पैट्रियट रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है,

सुमी शहरों को भी निशाना बनाया, जिसमें हर हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के अनुसार, कीव पर हुए हमलों से पांच जिलों में आग लग गई, जिससे रिहायशी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक साइटों, एक डॉरमिटरी और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 32 साल की विक्टोरिया शेजको अपने सात बच्चों और पति के साथ अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के कॉरिडोर में शरण ले रही थीं, तभी उन्होंने जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि जब सायरन बजा, तो हमने चेक किया कि बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, फिर हम कॉरिडोर में चले गए। उसके बाद एक के बाद एक मिसाइलें फटने लगीं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बमबारी का तनाव मानसिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। पहले यह हमले में एक बार या उससे भी कम होता था,

लेकिन अब अगर रोज नहीं, तो हर दूसरे दिन ऐसा होता है। बचाव दल ने स्वियातोशिरंस्की जिले में आग लगे एक घर से चार लोगों को बाहर निकाला, जबकि शेवचेंकिव्स्की जिले में वे आग लगी तीन मंजिला इमारत से निवासियों को बचाने के लिए पहुंचे। वहां एक व्यक्ति मृत पाया गया। फायरफाइटर्स ने सोलोमियांस्की, डेसनिंयांस्की और निग्रो जिलों में लगी आग को बुझाने का काम भी किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कीव पर हमले में यूक्रेनी सेना से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया — इनमें प्लेमिंगो ड्रोन और नेपच्यून गाइड्ड मिसाइल के पादर्स बनाने वाले प्लॉट, साथ ही दोहरे इस्तेमाल वाले सामान को रखने और ड्रोन, रोबोटिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वियपमेंट को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पोस्टल टर्मिनल शामिल था।

अमेरिका के हमले से दहला ईरान, हवाई हमले तेज, जंग के मुहाने पर मिडिल ईस्ट?



वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने आज तड़के कहा कि उसने ईरान को निशाना बनाते हुए हवाई हमलों का एक नया दौर शुरू किया है।

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की घोषणा की, जो लगातार नौवीं रात भी जारी रहे। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, ये

आम नागरिकों (नाविकों) पर हमले के लिए किया जाता है। अमेरिका ने रविवार को ईरान पर और हवाई हमले शुरू करते हुए एक और सैनिक की मौत की घोषणा की। ये हमले अमेरिकी सैनिकों की हत्या के जवाब में किए गए थे। वहीं, ईरान ने जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागीं, जिससे संघर्ष के पड़ोसी देश इजराइल तक फैलने का खतरा पैदा हो गया।

दोनों पक्षों ने जरूरी बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना

धीरे-धीरे, अमेरिका और ईरान पूर्ण युद्ध के करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि पिछले महीने लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए हुआ अंतरिम समझौता टूट गया है और होमुंज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही काफी हद तक रुक गई

है। दोनों पक्षों ने आम नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं।

जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला

अमेरिकी सेना ने बताया कि शनिवार को इराक में एक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे निर्यंत्रित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई। इससे पहले, सेना ने कहा था कि उसके हमलों का मकसद ईरान के अर्धसैनिक रिजोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाना था, जो जॉर्डन में शुक्रवार को सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था। उस हमले के बाद एक सैनिक लापता हो गया था, और सेना के नए बयान में कहा गया है कि रविवार को अज्ञात अवशेष मिले हैं

जिनकी जांच की जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 17 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं।

इजराइली इलाके में भी फैल रही जंग की आग

गोलाबारी का यह नया दौर अब दूसरे हफ्ते में है, जिसमें अमेरिका ने ईरान में पुलों, पानी की खारापन-मुक्त करने वाले संयंत्रों और बिजली सुविधाओं को निशाना बनाया है। तेहरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए हैं। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन ने ईरान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों के लिए फिर से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। इजराइल ने चेतावनी दी कि पड़ोसी जॉर्डन की ओर दागी गई मिसाइलों के कारण हफ्तों में पहली बार इजराइली इलाके में भी आग फैल सकती है।

तेहरान, एजेंसी। भारत ने रविवार को अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे सुरक्षा हालात सुधरने तक ईरान की यात्रा टाल दें। साथ ही, बढ़ती अस्थिरता और टकराव के बीच जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं, उनसे उपलब्ध कमर्शियल उड़ानों के जरिए वहां से निकलने पर विचार करने को कहा। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और टकराव बढ़ा है, इसलिए भारतीय नागरिकों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय दूतावास ने कहा, जो भारतीय नागरिक किसी भी मकसद से ईरान जाना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए, जब तक कि सुरक्षा हालात बेहतर न हो जाएं। इसने ईरान में मौजूद भारतीयों को सलाह दी कि वे उपलब्ध उड़ानों

बंगाल के सरकारी दफ्तरों में अब सिर्फ बंगाली भाषा में होगा काम, 1 सितंबर से बदलेगा नियम

सीएम शुभेंदु का बड़ा फैसला

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार 1 सितंबर से सभी सरकारी कामों के लिए बंगाली भाषा को अनिवार्य कर देगी। ये फैसला राज्य के सरकारी कामों के लिए लिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत के लिए हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार 1 सितंबर से सभी तरह के पब्लिक कम्युनिकेशन चैनलों पर बंगाली भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य कर देगी। इसमें नागरिकों के लिए सेवार्प, डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम, एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट, पोर्टल, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रेनिंग का सामान, पब्लिक साइनबोर्ड, प्रेस रिलीज और दूसरी आधिकारिक बातचीत शामिल हैं।

‘मंटो ने मुश्किल दौर से बाहर निकाला’, रसिका दुग्गल बोलीं- ऑडिशन से नहीं होती दिक्कत, रिजेक्शन पर कही ये बात



रसिका दुग्गल ने गहरे और हटकर किरदारों को चुनकर अपना करियर बनाया है। लेकिन वह मानती हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका करियर किस दिशा में जा रहा है। जहां 'मिर्जापुर' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं रसिका का कहना है कि 'मंटो' ने उन्हें उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। रसिका ने उन किरदारों के बारे में बात की जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बताया कि वह ऑडिशन देने से क्यों नहीं कारातीं।

इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अपने करियर के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रसिका ने कहा कि 'मिर्जापुर' वेशक सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंची। लेकिन 'मंटो' ऐसे समय में मिली जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लोगों ने मुझे एक अलग नजरिए से देखा और जो बहुत बड़े दर्शकों तक पहुंचा, वह निश्चित रूप से 'मिर्जापुर' था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज ने मुझे उस मुश्किल दौर से बाहर निकाला, वह 'मंटो' थी। 'किस्सा' और 'मंटो' के बीच सच में एक लंबा पैथ था और मुझे ज्यादा काम नहीं मिल रहा था। उस समय मुझे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जो बहुत मुश्किल था। वह सच में ऐसा दौर था जब मुझे लगता था, 'अब यहां से आगे क्या? अब मैं कहाँ जाऊँ? किस दरवाजे पर दस्तक दूँ और किससे पूछूँ?'

मुझे ऑडिशन देने में कोई दिक्कत नहीं

इंडस्ट्री में दो दशक से ज्यादा समय बिताने के बावजूद रसिका कहती हैं कि उन्होंने कभी भी ऑडिशन देने को अपने स्तर से नीचे नहीं समझा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ऑडिशन दूँगी। पिछले कुछ साल में लोगों ने मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर वे कहते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं खुशी-खुशी ऐसा करूँगी क्योंकि इससे मुझे और उन्हें उस रोल में मुझे देखने का मौका मिलता है। मुझे यह जानने का भी मौका मिलता है कि वे क्या चाहते हैं। तो यह दोनों के लिए फायदेमंद है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है।

खुशकिस्मत हूँ की टाइपकास्ट नहीं हुई

रसिका का कहना है कि वह खुशकिस्मत रहीं कि एक ही तरह के किरदारों में बंधकर नहीं रह गईं। 'मिर्जापुर' में एक्टर्स को उनके किरदारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं लकी थी क्योंकि 'मंटो', 'मिर्जापुर' और 'दिल्ली क्राइम' लगभग एक ही समय पर रिलीज हुए थे।

'दिल्ली क्राइम' और 'मिर्जापुर' में बिल्कुल अलग-अलग किरदार थे। इसलिए मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे उस विविधता को आजमाने और दिखाने का मौका मिला।

'दिल्ली क्राइम' एक बहुत ही शानदार शो है। रसिका ने माना कि टाइपकास्टिंग से बचना हमेशा उनकी प्राथमिकता नहीं थी। अपने करियर के शुरुआती कुछ साल में एक ही तरह के रोल में बंधे रहने की चिंता करने के बजाय काम मिलना ज्यादा जरूरी था। करियर की शुरुआत में मैं सोचती थी, 'चलो स्टूडियोटाइप ही सही, लेकिन कम से कम काम तो मिलेगा।' मैं सच में यह नहीं सोच रही थी कि 'अगर मैं एक ही तरह के रोल में बंध गई तो क्या होगा?' मैं बस यही सोच रही थी कि 'मुझे बस काम करना है।'

रिजेक्शन या सफलता दिल से नहीं लगाना चाहिए

रिजेक्शन को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि इतने साल में मैंने सीखा है कि हर रिजेक्शन या हर सफलता को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अनुभव से पता चलता है कि यह पूरी तरह से आप पर निर्भर नहीं है। जब चीजें ठीक से नहीं होतीं तो आपको इसे इतना व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। जब चीजें ठीक हो जाती हैं, तो आप उसका पूरा श्रेय भी नहीं ले सकते। यह सब किस्मत की बात है। फिर भी, जब कुछ अच्छा

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि आज मैं आयोग की रिपोर्ट जारी कर रहा हूँ, जिसे 2011 में TMC सरकार के दौरान जस्टिस सुशांत चटर्जी की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1 सितंबर 2026 से सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि भूमि और भूमि सुधार विभाग से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक का कामकाज बांग्ला भाषा में होगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सेवाओं, हलफनामों, ऐप्स, नागरिक चार्टर, FIR और नोटिफिकेशन के लिए बांग्ला का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्री और विधायक शुभेंदु अधिकारी को 1 हफ्ते के अंदर पत्र का जवाब देना होगा। एक लिस्ट CMO को भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दूँगा।

शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पत्र लिखकर प्रशासन में बंगाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री ने शाह के पत्र से पढ़कर सुनाया, "यह साल भारत के महान शिक्षाविद, राजनेता और गहरे विचारक डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का साल है।" उन्होंने विधानसभा में पढ़कर सुनाया, "डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और व्यापक इस्तेमाल के जबरदस्त समर्थक थे। उनका पक्का मानना था कि भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में अपना सही स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तभी असरदार और जन-केंद्रित हो सकती है जब वह लोगों की अपनी भाषा में काम करे।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से उसी दिन मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया था। वकील का कहना था कि संबंधित अधिकारी संपत्ति को गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि निर्माण के लिए

‘आज ही बिल्डिंग गिरा दी जाए, तब भी सुनवाई नहीं की जाएगी’, बुलडोजर एक्शन पर बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस



स्वीकृत भवन योजना मौजूद है, बावजूद इसके अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट को

बताया कि संपत्ति तालाब वाले इलाके में बनी बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए मंजूरी वाला प्लान मौजूद था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का आरोप है कि संपत्ति का निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भवन का निर्माण विधिवत स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया है

CJI सूर्यकांत ने क्या कहा

हालांकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले में तत्काल सुनवाई करने और किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 'भले ही इसे आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा।' उन्होंने स्पष्ट किया कि

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहली बार में विचार नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा और पार्टियों द्वारा हाईकोर्ट को दरकिनार कर तत्काल राहत पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की आदत पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में राहत पाने के लिए पहले संबंधित हाईकोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई करने से साफ मना कर दिया।

‘मुस्कुराती है तो खूबसूरत, वर्ना आग’, ‘वाराणसी’ से सामने आया प्रियंका चोपड़ा का नया लुक, राजामौली ने दिखाई झलक

एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का एक नया लुक सामने आया है। इससे पहले उन्हें मंदाकिनी के किरदार में इंद्रोइयूस किया गया था। अब मेकर्स ने फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का नया लुक जारी किया है। खुद निर्देशक एसएस राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के नए लुक की तस्वीरें साझा की हैं। राजामौली ने प्रियंका की दो तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें एक में वो ब्लैक कलर के आउटफिट में गुस्से में नजर आ रही हैं।

जबकि दूसरी तस्वीर में प्रियंका मुस्कुराती हुई उछलती-नाचती दिख रही हैं। इस नए लुक को जारी करते हुए राजामौली ने कैप्शन में लिखा, 'जब वह मुस्कुराती है तो विनम्र, जब वो ऐसा नहीं करती है, तो आग है। वाराणसी में मंदाकिनी के किरदार में प्रियंका चोपड़ा।'

प्रियंका चोपड़ा का ये नया लुक उनके जन्मदिन के मौके पर जारी किया गया है। कैप्शन से मंदाकिनी के किरदार के बारे में राजामौली की सोच का पता चलता है, जिसमें नजाकत और मजबूती दोनों ही झलकती हैं। कहानी की डिटेल्स बताने के बजाय फिल्ममेकर ने उनके अलग-अलग गुणों को उभारने का फैसला किया, जिससे पता चलता है कि यह रोल कमजोरी और अटूट मजबूती के बीच संतुलन बनाता है।

प्रियंका का लुक बहुत गंभीर और प्रभावशाली है, जो एक गहरे और दमदार किरदार की ओर इशारा करता है। मंदाकिनी को दुनिया भर में घूमने वाली एक जबरदस्त किरदार के तौर पर बताया गया है, जो मजबूत और संवेदनशील होने के साथ-साथ यादगार भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह किरदार फिल्म की कहानी में अहम भूमिका निभाता है।

इस हफ्ते ने ऐसा इक्का चलाया कि धमाल ही मच गया : संजीदा शेख

अभिनेत्री संजीदा शेख इन दिनों अपनी फिल्म धमाल-4 और इक्का की रिलीज का लुत्फ उठा रही हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अलग-अलग समय पर बनी फिल्में एक ही दिन रिलीज हो जाएंगी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस खास पल को अנוखा बताया। अभिनेत्री संजीदा शेख ने शब्दों से खेलते हुए लिखा, इस हफ्ते ने ऐसा इक्का चलाया कि धमाल ही मच गया। क्या शानदार और यादगार हफ्ता

रहा। किस्मत भी कभी-कभी बहुत खूबसूरत तरीके से चीजों को जोड़ देती है। अलग-अलग समय पर शूट की गई धमाल 4 और इक्का एक ही दिन रिलीज होंगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था।

अभी भी इस एहसास को महसूस कर रही हूँ। दर्शकों द्वारा मिले प्यार, खुशी और सम्मान के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं अभी इस प्यार को पूरी तरह महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी के प्यार और हौसला बढ़ाने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका प्यार मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। शुक्रिया। फिल्म धमाल-4 में संजीदा शेख अहम भूमिका में नजर

आ रही हैं। फिल्म में वह अरशद वारसी (आदि) और जावेद जाफरी (मानव) की जोड़ी वाली तीसरी टोली का हिस्सा हैं, जहां वह भाभी (आदि की पत्नी) का किरदार निभा रही हैं।



एसी होगी ‘वाराणसी’ की कहानी

'वाराणसी' एसएस राजामौली की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक होने वाली है, जिसमें साईंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल और भारतीय पौराणिक कथाओं का ग्लोबल स्तर पर मेल देखने को मिलेगा। फिल्म में महेश बाबू भगवान शिव के परम भक्त 'रुद्र' की मुख्य भूमिका में हैं। जबकि फिल्म के एक हिस्से में वो भगवान राम के किरदार में भी दिखेंगे। कहानी एक शक्तिशाली कॉस्मिक चीज को वापस पाने के लिए सदियों और महाद्वीपों में फैली उनकी

खतरनाक यात्रा के बारे में है। हालांकि, उनके मिशन में एक बड़ा मोड़ तब आता है, जब उन्हें पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा निभाए गए किरदार 'कुंभा' के असली इरादों का पता चलता है, जो उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहता है।

7200 BCE से लेकर 2071 तक के समय को समेटने वाली इस एपिक फिल्म में रामायण से प्रेरित 30 मिनट का एक अहम हिस्सा भी है। यह दर्शकों को अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों और अफ्रीका के जंगलों से लेकर वाराणसी के आध्यात्मिक केंद्र तक ले जाती है। 'वाराणसी' अगले साल 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी है।

